

फरीदाबाद

मजदूर समाचार

मजदूरों के अनुभवों व विचारों के आदान-प्रदान के जरियों में एक जरिया

नई सीरीज नम्बर 112

अक्टूबर 1997

क्यों जानें ? क्या-क्या जानें ? कैसे जानें ? क्या-क्या कर सकते हैं ? (9)

टिकी है भरोसों पे उल्टी ये दुनियाँ

- ट्रेन-बस की टिकट भरोसा लिये है टिकट पर कि उतारा नहीं जायेगा राह में।
- डाक टिकट चिट्ठी पर भरोसा लिये है टिकट पर कि पहुँचाया जायेगा सन्देश।
- पैसा रखना बैंक में लिये है भरोसा बैंक पर कि लौटाया जायेगा डिमान्ड पर।
- तनखा लेना नोटों में भरोसा लिये है नोटों पर कि कागज के उन टुकड़ों के बदले ले सकते हैं रोटी, कपड़ा और मकान।
- नौकरी करना लिये है भरोसा कि मिलेगी तनखा।

अगर ये भरोसे टूट जायें तो क्या हो? टिकट-विकट, बैंक-वैंक की तो छोड़ो, नौकरी ही कोई क्यों करेगा-करेगी। बिना नौकर-चाकर के साहब कैसे रहेंगे। चलेगी कैसे ये भेड़चाल भरोसे के बिना।

अधिकांश लोगों के लिये जलालत की जिन्दगी लिये यह दुनियाँ उल्टी नहीं तो क्या है? और यह उल्टी दुनियाँ भरोसों की नींव पर टिकी है। ऊँच-नीच की सीढ़ी के ऊपर वाले डंकों पर विराजे साहबों के लिये इन भरोसों को बनाये रखना अस्तित्व का सवाल है।

भरोसों का डगमगाना साहबों पर भारी दबाव डालता है। इसलिये भरोसों पर शंका पैदा करने वाली घटनाओं को साहब लोग छिपाते फिरते हैं। हम छिपाने न दें,

डुगडुगियाँ बजायें, बातें फैलायें तो साहब लोगों के लिये जरूरी हो जाता है कि हमें रियायतें दें ताकि भरोसों को बनाये रखा जा सके। भेड़चाल चले कैसे भरोसे के बिना?

महीने-भर काम करने के बाद तनखा मिलेगी के भरोसे पर मजदूर नौकरी करते हैं। फरीदाबाद की हजारों फैक्ट्रियों में तीन लाख मजदूर इस भरोसे पर नौकरी कर रहे हैं। लेकिन सैकड़ों फैक्ट्रियाँ यहाँ ऐसी हैं जहाँ दो-तीन-पाँच-आठ-अठारह महीनों से मैनेजमेन्टों ने मजदूरों को तनखायें नहीं दी हैं। चन्द नाम हैं: बल्लभगढ़ रिफ़ैक्ट्री लिमिटेड, प्रताप स्टील, हरियाणा ड्रैक्टर्स, रेमिंग्टन, झालानी टूल्स, अमेटीप मशीन टूल्स, हितकारी पोर्ट्रीज। 15-20 दिन देरी से तनखायें दिया जाना आम बात बन गई है। तनखा माँगने पर धमकी, चार्जशीट-सस्पेंड, तालाबन्दी करना मैनेजमेन्टों का रूटीन कार्य बन गया है। मजदूरों के ज्यादा पैसे बकाया होने पर क्लोजर भी किया जाता है।

जिन मजदूरों के पैसे अटकते होते हैं वे पहले तो मैनेजमेन्ट पर भरोसा रखते हैं। यह भरोसा टूटने पर वे लेबर डिपार्टमेन्ट पर भरोसा करते हैं। इसके टूटने पर डी.सी. पर भरोसा, मंत्री पर भरोसा करते हैं। इनके भी टूटने पर अदालत पर भरोसा। इन सब भरोसों का संगी-साथी है लीडरों पर भरोसा। अदालतों की लम्बी तारीखों और लीडरों के दीर्घ आश्वासनों पर भरोसों के टूटने तक मजदूरों के पैसे डूब चुके होते हैं। यह नतीजा है मैनेजमेन्ट, लेबर डिपार्टमेन्ट, डी.सी., मंत्री, अदालत, लीडर पर भरोसों का।

मैनेजमेन्ट, लेबर डिपार्टमेन्ट, डी.सी., मंत्री, अदालत, लीडर पर भरोसों की वजह से जो मजदूर भुगत रहे होते हैं वे अन्य फैक्ट्रियों के मजदूरों को अपनी बातें नहीं बताते। अन्य मजदूरों में तनखा मिलने का भरोसा कायम रहता है। इसलिये हजारों फैक्ट्रियों के साहबों

पर असर नहीं पड़ता। इसीलिये सरकारी साहबों पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ता। बड़ी संख्या में मजदूरों का तनखा मिलने पर भरोसा बने रहने की वजह से साहबों को रियायत देने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती।

लेकिन फँसे मजदूर अगर डगर-डगर पर डुगडुगियाँ बजायें, आठ-दस की टोलियों में शिफ्टों के समय बीसियों सड़कों पर गतों पर अपनी बातें लिख कर खड़े हो जायें, लन्च के समय टोलियों में दर्जनों फैक्ट्रियों के गेटों पर जायें तो दस-बारह दिन लगातार ऐसा करने पर लाखों मजदूरों के भरोसे डगमगाने लगेंगे। साहबों की, साहबों के साहबों की और उनके साहबों की नींद उड़ जायेगी। साहब लोग भारी दबाव में आ जायेंगे क्योंकि लाखों मजदूरों का भरोसा डगमगाने से ऊँच-नीच की सीढ़ी डगमगाने लगेगी और उनके आसन अस्थिर हो जायेंगे। इसलिए भरोसे बनाये रखने की अपनी बुनियादी जरूरत पूरी करने के लिये साहब लोग फँसे मजदूरों को रियायत देने को मजबूर हो जायेंगे।

“मजदूर मजदूर की मदद करें” के प्रवचन और उन पर शंकायें वास्तव में कोई मुद्दा नहीं है। भरोसा टूटना ही असल बात है क्योंकि बड़ी संख्या का भरोसा उठ जाना इतना प्रेशर लिये है कि वैसा नहीं होने देने के लिये साहब लोगों के लिए मजदूरों के छोटे हिस्से को रियायत देना बेहतर है। भरोसों के डगमगाने से नहीं चलेगी भेड़चाल।

Published

Reflections on Marx's Critique of Political Economy

The book is free.

इस अंक की हम पाँच हजार प्रतियाँ ही फ्री बाँट पा रहे हैं। पाँच हजार मजदूर अगर हर महीने एक-एक रुपया दें तो दस हजार प्रतियाँ फ्री बाँट सकेंगी।

मजदूर लाइब्रेरी, आटोपिन झुग्गी, एन. आई. टी. फरीदाबाद-121001 (यह जगह बाटा चौक और मुजेंसर के बीच गंदे नाले की बगल में है।)

ई एस आई अस्पताल

11 सितम्बर को पिता के साथ स्कूल से लौटते समय सात वर्षीय सुनीता साइकिल से गिर गई। सुनीता के पिता कटार सिंह मलिक व्हर्लपूल फैक्ट्री में काम करते हैं। वे अपनी लड़की को ले कर तीन नम्बर में ई एस आई अस्पताल गये। हड्डियों के डॉक्टर ने एक्सरे करवाने के बाद बताया कि सुनीता के पैर की हड्डी टूट गई है। प्लास्टर चढ़ाने के लिये डॉक्टर ने शाम को 6 बजे बुलाया। 6 बजे पहुँचने पर डॉक्टर ने प्लास्टर चढ़ाने के लिये 1000 रुपये माँगे। कटार सिंह ने अपने ई एस आई कार्ड का हवाला दे कर रिश्वत देने से इनकार कर दिया। इस पर डॉक्टर ने वार्ड में भर्ती करने और फुर्सत मिलने पर प्लास्टर चढ़ाने की बात कही। सुनीता की हालत देख कर कटार सिंह ने हड्डियों वाले डॉक्टर को उनके गलत व्यवहार की बात कही तो डॉक्टर गर्म हो गये और धक्का-मुक्की की। सुनीता का प्राइवेट डॉक्टर से इलाज कराना पड़ा।

(डी.सी. को लिखे अपने पत्र की कॉपी व्हर्लपूल वरकर कटार सिंह ने हमें भी दी है।)

प्रोविडेंट फंड

श्रम मन्त्रालय ने घोषणा की है कि हर हालत में मजदूर को उसका प्रोविडेंट फंड का पैसा फार्म भरने के 30 दिन के अन्दर-अन्दर मिल जायेगा। इस पर 20/7 मथुरा रोड़ स्थित रेमिंग्टन रैण्ड के मजदूरों ने थोक में फार्म भरे। काम करने के बावजूद 5 महीनों से तनखा नहीं दिये जाने से रेमिंग्टन के 35 मजदूरों ने 30 जुलाई को, 7 मजदूरों ने पहली अगस्त को, 12 ने 12 अगस्त को और 3 ने 27 अगस्त को भविष्य निधि में जमा अपने पैसे निकलवाने के लिये पी.एफ. कार्यालय सैक्टर-15 में फार्म जमा किये। एक माह बाद पता करने पर सब फार्म वैसे ही पड़े मिले। काफी मिन्नतों के बावजूद कई फार्मों पर 10 सितम्बर तक आइटम नम्बर तक नहीं डाला गया। पी. एफ. कमिश्नर से रेमिंग्टन वरकरों ने मिलना चाहा तो मैडम ने धमका कर बाहर कर दिया। एक अन्य अधिकारी मिस्टर आर्य ने चपरासी के जरिये रेमिंग्टन मजदूरों को बाहर किया। पाँच महीनों से तनखा नहीं दी गई है और ऊपर से पी.एफ. के अपने पैसे निकलवाने में भी धक्के खाने पड़ रहे हैं।

17 सितम्बर 1997

— रेमिंग्टन रैण्ड मजदूरों की प्रेस विज्ञप्ति

शिफ्ट वर्क - नाइट वर्क (2)

समाज के लिये एक व्यक्ति का कार्य अन्य के लिये उपयोगी होता है। समाज व्यवस्था की जरूरत की वजह से कई प्रकार के काम दिन की जगह रात को करवाये जाते हैं। इनके उदाहरण हैं: बड़े शहरों में दिन-भर व्यस्त रहते मार्गों की मरम्मत, मार्गों के नीचे की गटरों की सफाई आधी रात को करवायी जाती है। सुरक्षा, यातायात, चिकित्सा इमरजेंसी, होस्पिटल में दाखिल मरीजों का इलाज - ये सभी की जरूरतें चौबीस घन्टे रहती हैं। इस तरह ड्राइवर्स, सफाई कर्मचारी, पुलिस, गार्ड्स, डॉक्टरों, नर्सों आदि सब को रात को भी काम करना पड़ता है। कहीं पर सतत उत्पादन प्रक्रिया की वजह से ये काम चौबीस घन्टे करवाया जाता है। ये सब जगहों पर काम करवाना अनिवार्य है मगर अन्यत्र कई काम ऐसे भी हैं जिन्हें रात के समय करवाने की कोई जरूरत नहीं लगती फिर भी करवाये जाते हैं। इन सब के लिये जो विविध कारण सामने रखे जाते हैं वे हैं: रोजगार बढ़ाना, महंगे यन्त्रों का महत्तम उपयोग, बाजार में माँग बढ़ने से उत्पादन बढ़ाना, समाज को ज्यादा सुविधा देना (बैंक सेवा....)।

आदिकाल से मानव सूर्य के साथ, सूर्योदय से सूर्यास्त तक कार्यान्वित रहता था। वह भोर होते जागता था, दैनिक क्रियायें करके कामकाज करता था और शाम को ये प्रवृत्ति बन्द करके रात को आराम करता था। यही लयबद्धता मानव शरीर में स्थापित हो चुकी है। यह लय का नियमन पिच्युटरी नामक छोटी-सी अंतः स्त्रायी ग्रंथी मालाटोनीन नामक हॉर्मोन के स्त्राव से करती है।

अर्वाचीन युग में प्रकाश के उपकरणों, बिजली आदि का संशोधन हुआ। टेक्नोलॉजी में प्रगति होती रही मगर वह मानवीय न रही। मानव ने सूर्य के साथ लयबद्ध चल रहे शरीर को इस लय के विरुद्ध चलाने का प्रयास किया। मगर शरीर इस प्रकार सहकार नहीं दे सकता। शरीर जब आराम चाहता है तभी उससे काम लेने का प्रयास होता है। अन्ततः स्वास्थ्य का किसी न किसी तरह का जोखिम सहना पड़ता है। फिर भी औद्योगीकरण बढ़ने के साथ-साथ शिफ्ट वर्क - नाइट वर्क का व्यास बढ़ता ही जा रहा है।

(आगे अगले अंक में)

— नवीन छत्रोला, बड़ौदा

पिलखुआ नगरी (2)

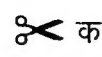


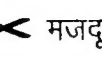
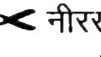
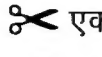
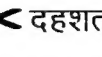
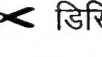
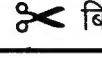
यहाँ 12 से 16-18 घन्टे काम करके भी वीवर ग्रेड या प्रिंटिंग ग्रेड नहीं मिल पाता है। जबकि किसी भी मजदूर की दिहाड़ी न्यूनतम ग्रेड से कम नहीं होनी चाहिए - कानून में जुर्माने के साथ 6 माह की सजा भी दी गई है। लेकिन यहाँ तो घरेलू उद्योग और पीस रेट के नाम पर अच्छा-खासा मजदूरों का शोषण मैनेजमेंट कर रही हैं और उत्तर प्रदेश सरकार व श्रम विभाग सब कुछ जानते हुये भी चूहे-बिल्ली वाला खेल खेल-रहे हैं। मजदूरों की हालत वह हो रही है कि दिन-भर भागो तो दियवा-भर और रात-भर भागो तो दियवा-भर जबकि भारत में ही नहीं पूरी दुनियाँ-भर में 8 घन्टे से ज्यादा की ड्युटी पर प्रतिबन्ध है। यदि कोई एक-दो घन्टे कराना भी चाहे तो कानूनन रेट डबल है। यहाँ तो काम डबल घन्टा है (8 से 16 घन्टा), पैसा पीस रेट के नाम पर न के बराबर। वाह बुद्धिजीवी लोग! क्या दिमाग पाया है! जहाँ भारत सरकार घोषणा करती है, कानून बनाती है कि 10 मजदूर पर फैक्ट्री एक्ट लागू है, पिलखुआ में शायद किसी भी फैक्ट्री में 10 मजदूर से कम नहीं बल्कि 50 से 100 मजदूर तक हैं और उत्तर प्रदेश सरकार श्रम विभाग के पास तो शायद पिलखुआ के हर कारखाने का नाम तक रिकार्ड नहीं होगा क्योंकि श्रम विभाग का यहाँ एक भी ऑफिस शायद नहीं है। फैक्ट्रियों में मशीनों का तो रिकार्ड होगा लेकिन मजदूरों का तो कोई रिकार्ड होना ही नहीं है क्योंकि यहाँ तो उनके घर का राज है। पिलखुआ के किसी भी कारखाने के खिलाफ शायद सरकार के पास आज तक एक भी केस दर्ज नहीं होगा। यहाँ पुलिस चौकी तो कई हैं लेकिन श्रम विभाग एक भी नहीं है जबकि पिलखुआ में मजदूरों की संख्या 50 हजार है। फिर भी यह देखा जा रहा है कि किसी भी कारखाने में पूरे कारीगर नहीं हैं। मजदूरों के चेहरों पर निराशा दिखती है। बातचीत से यह पता चला कि यहाँ कुछ नहीं होना है, आज यहाँ हैं कल कहाँ होंगे कुछ पता नहीं। वीवर हाई स्किल्ड कारीगर में आता है, वह आम मजदूरों से अलग हो जाता है। शारिरिक श्रम के साथ-साथ मानसिक श्रम भी करना पड़ता है। रोड़ से चलते हुये किसी आदमी से विविंग या प्रिन्टिंग का काम नहीं लिया जा सकता - सालों-साल कास सीखना पड़ता है।

बाल मजदूरी के ऊपर रोज बरोज सरकार टेलीविजन व रेडियो प्रोग्राम पेश करती रहती है कि बाल मजदूरी खत्म करो और बाल मजदूर रखने पर जुर्माना भी 25 हजार रुपये तक है और दुनियाँ की सरकारें बाल दिवस भी बनाती हैं। लेकिन पिलखुआ के अन्दर ऐसा कोई भी कारखाना नहीं है जिसमें बाल मजदूर, लड़के व लड़की जिनकी उमर 10-12 साल ही है, न हों। औरतों की संख्या भी काफी तादाद में है जो अपने दूध पीते बच्चों को साथ लिये होती हैं। फिर भी वे 10-12 घन्टे काम करती रहती हैं। कारखानों में बच्चों को रहने व खेलने के लिये अलग से कोई व्यवस्था नहीं है।

9 अगस्त 97 — पिलखुआ में एक मजदूर

मैनेजमेंटों के शिकंजे

मैनेजमेंटों के लक्ष्य

 काम की रफ्तार बढ़ाना  कम मजदूरों से ज्यादा काम करवाना  कम से कम वेतन देना  मजदूरों की मेल-जोल, पहलकदमियों को बिखेरना  नीरस को रंगीन दिखाना  एकताओं की रचना द्वारा मजदूरों में सिरफुटौवल करवाना  दहशत का माहौल बनाना  डिसिप्लिन, यानि, मजदूरों पर जकड़ को मजबूत करना  बिना नागा, हर पल काम करवाना, और बेशक अपना-अपना कट-कमीशन सुनिश्चित करना

वर्क सस्पेंड

अगस्त के वेतन की आस ले कर 11 सितम्बर को सुबह ड्युटी के लिये पहुँचे 21/3 मथुरा रोड़ स्थित प्रताप स्टील के मजदूरों को गेट पर वर्क सस्पेंड का नोटिस और ताला मिला। 23 सितम्बर को बातचीत से पता चला कि वर्क सस्पेंड का अर्थ है बिना किसी चार्ज के सब वरकर सस्पेंड, यानि तालाबन्दी कहे बिना तालाबन्दी।

21 आर्क फरनेस के साथ प्रताप स्टील लिमिटेड इस प्रकार की प्रमुख स्टील रोलिंग कम्पनी है। मंडी की दिक्कतों व मैनेजमेंट के कट-कमीशन-ट्रान्सफर नें इन चार-पाँच साल में कम्पनी के घाटे को 42 करोड़ रुपये कर दिया है जो कि कम्पनी में लगी पूँजी के बराबर है। ऐसे में मजदूरों को वेतन नहीं दे कर, वरकरों के प्रोविडेंट फन्ड और ई एस आई के पैसे जमा नहीं करके, रिटायर हुए मजदूरों को सर्विस-ग्रेच्युटी के पैसे नहीं दे कर लूटमार में लगी प्रताप स्टील मैनेजमेंट ने बैंकों से और कर्ज न मिलने तथा बिजली बोर्ड द्वारा ढाई करोड़ रुपये के बकाया के लिये कनेक्शन काट दिये जाने पर मजदूरों को गेट के बाहर धकेला है। बिना कुछ दिये हैदराबाद, इन्दौर, मंडी गोबिन्दगढ़, छिहरटा (अमृतसर) आदि में मजदूरों को फैक्ट्रियों से बाहर करके मैनेजमेंट ने फरीदाबाद फैक्ट्री में भी ऐसा ही किया है। कहीं से पैसे टपक पड़े तो मजदूरों को और झुका कर फैक्ट्री चलाने का भरोसा मैनेजमेंट ने दिया है।

1984 में फरीदाबाद फैक्ट्री में 1300 मजदूरों को हड़ताल के जरिये 250 कर चुकी प्रताप स्टील मैनेजमेंट अब वर्क सस्पेंड के जरिये मजदूरों के सर्विस-ग्रेच्युटी के पैसे भी हड़पने की फिराक में है। सरकारी साहबों के आश्वासनों के जाल और कोर्ट-कचहरी की तारीखों की दलदल मैनेजमेंट के आजु-बाजु संगी-साथी हैं।

नेगोसियेशन

“बात करो !”, “लीडरों से बात करो !” के नारे बेशक सिकुड़ गये हैं पर फिर भी “बातचीत चल रही है” के तिनकों में आँसुसागर पार कराने की अपार क्षमता है। नेगोसियेशनों के जरिये “कहो न आस निराश भई” की तर्ज पर मजदूरों को एक टाँग पर नचा कर ईस्ट इंडिया काँटन मिल मैनेजमेंट ने 12 सितम्बर को फैक्ट्री में तालाबन्दी का एक वर्ष पूरा किया। इस प्रकार सरकारी साहब और ईस्ट इंडिया मैनेजमेंट नेगोसियेशनों व एग्रीमेंट के जरिये कम्पनी की शर्तें मजदूरों पर थोपने के निकट पहुँच गये हैं।

ले ऑफ

ले ऑफ को छोटा झटका और तालाबन्दी को बड़ा झटका माना जाता है पर 4 सैक्टर स्थित प्रताप स्टील ग्रुप की हरियाणा ट्रैक्टर्स मैनेजमेंट ने 11 सितम्बर को किये ले ऑफ को 12 सितम्बर को तालाबन्दी में बदल कर एक के दूसरे में सहज रूपान्तरण का नजारा पेश किया है। दो महीनों के बकाया वेतन, जमा नहीं किये प्रोविडेंट फन्ड के संग-संग 150 मजदूरों की 15-20-25 साल की सर्विस-ग्रेच्युटी के पैसे हड़पने की फिराक में है मैनेजमेंट। 26 सितम्बर को हरियाणा ट्रैक्टर्स के मजदूरों में गुस्सा तो बहुत दिखाई दिया पर पिटी-पिटार्ड लीक छोड़ने की झलक कम ही दिखी। मजदूरों का सरकारी साहबों के आश्वासनों और तारीखों

के फेर में पड़ना मैनेजमेंट पर दबाव कम करता है।

विश्वकर्मा डे

पूजा एक अनुष्ठान है। 17 सितम्बर को विश्वकर्मा पूजा विधि-विधान अनुसार करने के लिये एस्कोर्ट्स मैनेजमेंट ने फस्ट प्लान्ट की शीट मैटल डिपार्टमेंट से मेन डाइयाँ निकाल कर ठेकेदारों के पास पहुँचा दी। 18 को ड्युटी पहुँचे तो शीट मैटल डिपार्ट के मजदूर अपनी नौकरी पर मंडराते खतरे को देख कर मैनेजर मूर्ति के पास गये। साहब ने आश्वासन दिया और वरकर छुट-पुट काम करने लगे। चन्द रोज बाद मिस्टर मूर्ति एस्कोर्ट्स से विदा हो गये

दरअसल एस्कोर्ट्स में मामला अधिक गम्भीर है। टी पी एम स्कीम लागू करने में असफल हो चुकी मैनेजमेंट इधर वी पी आर नाम की नई स्कीम पर काम कर रही है। लाइन सिस्टम वाली वी पी आर स्कीम में एक ही व्यक्ति को आपरेटर-हैल्पर-मेन्टेनैन्स वर्क के संग-संग इन्सपेक्शन तथा प्लानिंग का कार्य भी करना होगा। कई मिडल मैनेजर्स की छुट्टी के संग-संग एस्कोर्ट्स मैनेजमेंट की यह स्कीम मजदूरों की तबाही लिये है। वी पी आर लागू करने के लिये एग्रीमेंट एक जरिया नजर आती है और लीडरों के बीच का झगड़ा भारी दाँव का प्रतिबिम्ब हो सकता है।

स्वेच्छा उर्फ अनिच्छा

स्वेच्छा से सेवा निवृत्ति, यानि वी आर एस स्कीम के तहत सितम्बर के आरम्भ में कटलर हैमर मैनेजमेंट ने स्टाफ के 40 लोगों को नौकरी से निकाल दिया। एक-एक करके बुला कर मैनेजमेंट ने रिजाइन लिखवाई और धक्के से चौक दे दिये। जो नहीं माने उनसे जबरन दस्तखत करवाने के लिये कटलर हैमर मैनेजमेंट ने सेक्युरिटी का इस्तेमाल किया।

स्टाफ के बाद मैनेजमेंट ने मजदूरों का नम्बर लगाया। सितम्बर के तीसरे हफ्ते में तीन वरकरों को बुला कर मैनेजमेंट ने इस्तीफे लिखने को कहा तो शोर-शराबा हो गया। रिजाइन लिखवाना रोक कर कटलर हैमर मैनेजमेंट ने नेगोसियेशन शुरू कर दी है और मैनेजमेंटों के इस ब्रह्मास्त्र से मजदूरों का शिकार करने के लिये “बातचीत चल रही है”।

उलझाने को कोर्ट

1983 से बन्द पड़ी इन्डस्ट्रीयल एरिया स्थित मैटल बॉक्स के गेट पर सितम्बर में मजदूरों ने क्रमिक भूख हड़ताल शुरू की। हिसाब तो मैटल बॉक्स वरकरों को मिला ही नहीं है, उनका प्रोविडेंट फन्ड का पैसा भी अब तक नहीं मिला है। मैटल बॉक्स मजदूरों का पी.एफ. का पैसा कम्पनी के पास ही जमा होता था जैसे कि बाटा में होता है। फैक्ट्री बन्द कर दिये जाने पर मैटल बॉक्स मजदूर कम्पनी में जमा अपने प्रोविडेंट फन्ड के पैसे निकलवाने लगे तब मैनेजमेंट ने उकसा-उलझा कर कोर्ट केस करवा दिया। कोर्ट का फैसला होने तक मैटल बॉक्स मैनेजमेंट ने प्रोविडेंट फन्ड के पैसे भी देने से इनकार कर दिया। अदालत ने अब तक निर्णय नहीं दिया है।

अपनी
 बात खुद लिखें या
 हमें बतायें।

विरोध और बदलाव के ठुमके

☺ सरल कदम जो सब मजदूर हर रोज उठा सकते हैं ☺

मौन प्रतिरोध

मौन भड़का देता है लीडर को
तुम हो हमारे इलाके के
तुम हो हमारे जात के
तुमको हमने लगवायी है नौकरी
तुमको हमने दिलवाया है एडवांस

मौन भड़का देता है लीडर को
फलाने ने तुम्हें करवाया था सस्पेंड
हमने रखवाया है डिप्टी पर
चिलाने से तुम्हारी थी खुन्दक
हमने रक्षा की है तुम्हारी
इसलिये की तुम वोट दोगे हमें
इसलिये की तुम नोट दोगे हमें
और बनाओगे लीडर हमें

मौन भड़का देता है लीडर को
तुम्हें चलना होगा हमारे पीछे
तुम्हें सोचना होगा जो हम सोचें
तुम्हें करना होगा जो हम कहें
तुम्हें देखना होगा जो हम देखें

मौन भड़का देता है लीडर को
तुम्हें चाहियें लाख-डेढ लाख
तुम्हें चाहियें एल टी ए - बोनस
तुम्हें चाहियें वर्दी - जूते
तुम्हें सब दिलवायेंगे
तुम्हें जब उल्टा लटकायेंगे
नजारे सन चौरासी का करायेंगे

मौन भड़का देता है लीडर को
हमने कहा था चलो डी.सी. के पास
हमने कहा था चलो डी.एल.सी. के पास
हमने कहा था हस्ताक्षर करो उन समझौतों पर
जो लगात हैं लात तुम्हारे पेट पर

मौन भड़का देता है लीडर को
हमने तुम्हें पुचकारा था
हमने तुम्हें मना किया था
'गत्ता-नोटिस' लगाने से
कम्पनी की बदनामी होती है
बिन वर्दी चूतड़ दिखलाने से

मौन भड़का देता है लीडर को
तुमने हमारी बात नहीं मानी
तुमने हमारी कही नहीं सुनी
तुमने हमारी की अनदेखी

मौन भड़का देता है लीडर को।

2.10.97 - अशोक (झालानी टूल्स में मजदूरों
को 18 महीनों से वेतन नहीं दिये जाने से जुड़े
घटनाक्रम के सन्दर्भ में।)

विरासत

ट्रेन यात्रा के दौरान हल्की-फुल्की बातें हो रही थी। बगल में बैठा एक युवक कुछ समय पहले रिटायर हुये एक बुजुर्ग के किस्से सुनाने लगा। बातों में एक आधुनिक फैक्ट्री की काँइया मैनेजमेन्ट का जिक्र बार-बार आया। दरअसल वह युवक और जिस बुजुर्ग के किस्से वह सुना रहा था, वे दोनों एक बड़ी फैक्ट्री की मेन्टेनेन्स डिपार्टमेन्ट के मजदूर थे। युवा वरकर ने बताया: "उन्होंने 30 साल तक खुँखार मैनेजमेन्ट के सामने छाती तान कर नौकरी की। फुर्सत के क्षणों में वे हमें अपने गुर बताते थे। वे हमें बार-बार कहते थे कि किसी भी साहब को काम करने से मना मत करो। किसी मशीन से जूझ कर थकावट से चूर-चूर हो कर आये ही हो और बीड़ी सुलगाई ही है कि कोई साहब काम बताने लगता है तो भी बिदको मत। 'हाँ जी!' कहो पर कौन अपने ढँग से। जितने पुर्जों और जितने औजारों की जरूरत है वे सब माँगो। जुगाड़ मत बनो और पुर्जों व औजारों में कोई रियायत मत दो। साहब लोग स्वयं कन्नी काटने लगेंगे। काम का बोझ तो घटेगा ही, साहबों के रौब-दाब से छुट्टी भी मिलेगी।"

फ्री क्यों ?

आपसी बातचीत में हमें यह अक्सर महसूस होता है कि हमारे सब रिश्तों में पैसे ने तहलका मचा रखा है। दोस्तों के बीच रिश्ते, पड़ोसियों के साथ सम्बन्ध, भाई-बहन के रिश्ते, प्रेम के रिश्ते, पीढ़ियों के सम्बन्ध, स्त्री-पुरुष के रिश्ते, मनुष्य-मनुष्य के बीच के सम्बन्ध, सब मानवों के बीच रिश्ते, मनुष्य व प्रकृति के बीच सम्बन्ध पैसे के भंवरजाल में जकड़े हैं।

ऐसे माहौल में नये रिश्तों की उम्मीद लिये हम प्रयास कर रहे हैं। नये रिश्तों में रुपये-पैसे, ऊँच-नीच, रौब-दाब के लिये कोई जगह नहीं हो ऐसी हमारी कोशिश है। इसलिये हम कुछ लोग मिल कर अपने साधनों को जोड़ कर यह अखबार निकाल रहे हैं और सड़कों पर खड़े हो कर बाँट रहे हैं।

अखबार को फ्री बाँटते हुये हमें चार साल ही हुये हैं। इस दौरान हौसला बढ़ाने वाले जो भाव-रुख हमने देखे हैं उनसे मनुष्यों के बीच नये रिश्तों की सम्भावना में हमारा भरोसा बहुत बढ़ा है।

चाय-लड्डू फ्री

4-5 महीनों से एस्कोर्ट्स फर्स्ट प्लान्ट में मजदूर चाय-मट्ठी-लड्डू के पैसे नहीं दे रहे। बीच में कुछ लोगों ने पैसे देने शुरू किये थे पर फिर बन्द कर दिये। इधर कुछ दिन पहले परसनल मैनेजर ने डिपार्टमेन्टों में चक्कर लगा कर मजदूरों को हड़काते हुये कहा, "फ्री लेने में शर्म नहीं आती तुम्हें!" इस पर एक डिपार्टमेन्ट में एस्कोर्ट्स मजदूरों ने कहा, "साहब अपना ही घर है। अपने परिवार में शर्म कैसी? चाय-लड्डू तो छोटी चीज हैं, आखिर यह सब हमारी ही मेहनत के तो फल हैं।"

सम्पूर्ण सिंह

अच्छी-खासी हिन्दी बोल रहा एक तमिल मजदूर थोड़ा-सा टुन्न था। भावुक हो कर उसने बताया: "मद्रास में धड़ल्ले से चल रही पिता जी की चाय की दुकान लड़खड़ाने लगी। रोटी के लाले पड़ गये। नौकरी की तलाश में मैं दिल्ली आया। बुलन्दशहर में एक फैक्ट्री में मुझे काम मिल गया। एक दिन दिल्ली से फैक्ट्री के लिये एक मशीन ले कर मैं बस में बैठा। तब मुझे तमिल के अलावा थोड़ी अंग्रेजी आती थी पर हिन्दी बिलकुल नहीं आती थी। कन्डक्टर ने मुझे फैक्ट्री के पास उतारने की बजाय 6 किलोमीटर दूर उतारा। किसी तरह मशीन को धकेलता हुआ मैं चला। हिन्दी नहीं आने के कारण मैं किसी से मदद नहीं माँग सका। ऊपर से बरसात शुरू हो गई। मैं 'कोई है' जैसी आवाजें करता ठन्ड से काँपते हुये चलने लगा। तभी एक सरदार आया और मेरे से बातें की पर मुझे उसकी कोई बात समझ में नहीं आई और मैं उसे अपनी बात नहीं समझा सका। सरदार जी ने मेरे साथ मशीन उठाई और चले। रास्ते में एक ढाबे में उन्होंने मुझे गर्मागर्म खाना खिलाया। मशीन को उन्होंने फैक्ट्री गेट तक पहुँचवाया। उनका नाम सम्पूर्ण सिंह था। मैं सम्पूर्ण सिंह जी को 17 साल से ढूँढ रहा हूँ पर उसके बाद वे आज तक मुझे मिले नहीं हैं। सम्पूर्ण सिंह!"

Reprinted
a ballad against work

The book is free.